(b) what is the number of unemployed trained teachers in the country as on 31st January, 1987?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) The National Policy on Education 1986 envisages setting up of District Institutes of Education & Training (DIET) for preservice and inservice training of elementary School teachers and to provide academic expertise at district level. The scheme for setting up DIETs is being finalised in the Ministry.

(b) According to the data available with the Ministry of Labour, Director General, Employment and Training (D.G.E.&T), the number of teachers on the live registers of employment exchanges is as below. However, it may be clarified that all the teachers on the live register of employment exchanges are not necessarily unemployed.

Description	Number as on 31-12-1985	Number as on 30-6-1986
1. Graduates (including Post Graduates) in Education . . .	2,25,898	2,48,302
2. All job-seekers registered as teachers (trained and untrained) . .	5,82,707	NA

व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त छात्रों का भविष्य

2489. **श्री सोहन लाल धूसिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त छात्रों के भविष्य की सम्भावनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार इन छात्रों के भविष्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इस आशय की संकल्पना है कि व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी विशिष्ट शिक्षा होगी जिसका आशय छात्रों को क्रिया कलाप के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त मान्यता प्राप्त व्यवसायों के लिए तैयार करना है । देश के विभिन्न भागों में इस समय 115 विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किये जा रहे हैं जो छात्रों को वेतन के साथ-साथ स्वयं रोजगार के लिए तैयार करते हैं । ये पाठ्यक्रम मुख्यत: कृषि, भू-उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, गृह, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परा चिकित्सा और अन्य तकनीकी व्यावसायों के क्षेत्र में है । आर्थिक विकास में हुई वृद्धि से कुशल जनशक्ति की मांग बढ़ रही है जो व्यावसायिक स्नातकों से पूरी हो सकती है ।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना में केन्द्रीय और राज्य स्तरों की सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों में चयन के लिए भर्ती नीति में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है ताकि व्यावसायिक स्नातकों को उनकी अर्हताओं के अनुसार उनके लिए उचित पदों पर अधिक ध्यान दिया जा सके, सेतु पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकें तथा व्यावसायिक स्नातकों के वृहद व्यावसायिक प्रोन्नति के लिए अधिक परिस्थिति पैदा करने के लिए, विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमों में संशोधन किया जा सके । व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को वृत्तिका भोगी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, प्रशिक्षुओं की एक पृथक श्रेणी का सृजन करने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है । यह कार्यरत प्रशिक्षण उन्हें लाभप्रद वेतन और स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए उनकी

अपेक्षित निपुणताओं का विकास करने में सहायक होगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरारों के लिये आवास सुविधा

2490. **श्री सुशील कुमार पट्टनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरारों को आवास-सुविधा प्रदान किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विश्वविद्यालय में ऐसे कुल कितने लेक्चरार हैं जिनके पास आवास नहीं हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण की एक योजना 3.00 करोड़ रुपये की लागत पर, अनुमोदित की गई है और उसका कार्यान्वियन किया जा रहा है ;

(2) दिल्ली कालेजों के लिए 6.00 करोड़ रुपये की लागत वाली गृह निर्माण की एक अन्य योजना अनुमोदित की गई है और उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है ; और

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गृह-निर्माण अग्रिम के प्रावधान को 50.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक कर दिया है जिसका उपयोग आवर्तक निधि के रूप में किया जाना है ।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, कुल लगभग 5250 शिक्षकों में से 1085 शिक्षक, 1-7-1986 की स्थिति के अनुसार बिना आवास के हैं ।

Dereservation of posts in the Ministry

2491. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of posts dereserved in the Ministry of Communications in each cadre since 1981, year-wise; and

(b) whether the reservation rules are applicable in the Mahanagar Telephone Nigam Ltd.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) The number of posts dereserved in respect of the Department of Telecommunications (Telecom. Board) since 1981 is given below year wise:—

Year	A	B	C	D
1981	49	..	80	7
1982	..	43	59	2
1983	3	..	60	3
1984	..	..	180	1
1985	47	230	396	21
1986	..	..	101	1

(Information concerning the Department of Telecom. (other than Telecom. Board) and the Department of Posts is being collected and will be laid on the table of the house).